*वर्ष 2018 में जब लॉस एंजलिस के पश्चिम में वूलसी वाइल्डलाइफ फायर का आतंक फैला तो वहाँ रहने वाली कई नाम चीन हस्तियों को बचाकर निकाला गया। इनमें से माइली सायरस, जैरार्ड बटलर और नील यंग जैसी हॉलीवुड हस्तियों के घर तो पूरी तरह जल गए थे। चार साल बाद इनमें से अधिकांश हस्तियाँ फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, पर यहां के कई निवासी अब भी उस आग का दुष्परिणाम झेल रहे हैं, इनमें प्रमुख हैं कूगर। लॉस एंजलिस (एल.ए.) के आस-पास माउन्टेन लायन (कूगर) को ट्रैक कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि, पहले से ही जगह की कमी झेल रहे और परिणामस्वरुप सड़कों पर आवागमन के लिए बाध्य इन बड़े जानवरों ने वूलसी फायर के बाद और अधिक खतरे उठाने शुरु कर दिए हैं। वैज्ञानिकों ने जी.पी.एस. कॉलर्स की मदद से सैंटा मोनिका पहाड़ियों में लगी आग से पहले और बाद की, कूगर की गतिविधियों की तुलना की तो पता चला कि इन जानवरों ने आधे से ज्यादा अपने वो पूर्व आवास त्याग दिए हैं जहां आग लगी थी। इस घटना के बाद से ये अब और ज्यादा खतरा उठाने लगे हैं, जैसे हाइवे क्रॉस करना, दिन दहाड़े खुले आम घूमना आदि। इससे, इन जानवरों के दुर्घटना ग्रस्त होने और मरने का खतरा बढ़ गया है। विश्व के बड़े शहरों में सिर्फ एल.ए. और मुम्बई ही हैं, जहां बिगकैट्स शहर की सीमा के भीतर रहते हैं। नैशनल पार्क सर्विस व इसके सहयोगी दो दशकों से कैलिफोर्निया की सैंटा मोनिका पहाड़ियों के आस-पास तथा सैंटा सुज़ैनास व सैंटा एना में रहने वाले कूगर का अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 1.8 करोड़ लोगों के समीप रहना वैसे भी कूगर के लिए गंभीर खतरा है। सैंटा मोनिका पहाड़ियों का एक क्षेत्र, जो यू.एस. हाइवे 101 के दक्षिण में है, वहां 8 नर कूगर रहते हैं, जबकि यह क्षेत्र एक या दो कूगर के रहने योग्य ही है। ऐसी छोटी जगहों में कूगर का आपसी टकराव बहुत बड़ा खतरा है और अल्प वयस्क कूगर की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर पूर्ण वयस्क कूगर द्वारा वयस्क मादा व उसके शावकों को मार डालने की कई घटनाएं हुई हैं। भारी यातायात वाली सड़कों की वजह से इनके प्राकृतिक आवास विखंडित हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो स्थानीय आबादी लुप्त हो जाएगी। एक शोध में सैंटा मोनिका व सैंटा एना पहाड़ियों के कूगर में अन्तः प्रजनन के चिंताजनक संकेत भी मिले, जिसकी वजह से कुछ कूगर में विकृतियां पाई गई हैं। नई रिसर्च के अनुसार वूलसी फायर ने पहले से संकट ग्रस्त कूगर आबादी के लिए संकट और बढ़ा दिया है।*

# 'कोटपूतली नगर परिषद के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही क्यों ना की जाये?'

## राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटपूतली नगर परिषद द्वारा बिना नोटिस दिये मकान और दुकान को ध्वस्त करने से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा से जवाब तलब किया

- **जैसा कि विदित है कि हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को याचिकाकर्ता को राहत देते हुए नगर परिषद को आदेश दिये थे कि वह एक माह में संबंधित पार्टियों को नोटिस दे और उनकी आपत्तियों की सुनवाई करे तथा उसके बाद ही कोई कार्यवाही करे।**
- **याचिकाकर्ता का कहना है कि, नगर परिषद ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार कोई भी नोटिस नहीं दिये और अगस्त माह में उनका घर 25 फीट तक तोड़ दिया।**

जयपुर, 7 नवम्बर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में कोटपूतली नगर परिषद द्वारा सरदार स्कूल रोड के पास शनि मंदिर के समीप की दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ करने से संबंधित एक मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव तथा मनोज भारवानी की खंडपीठ ने कोटपूतली नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा को नोटिस जारी किये हैं और उनसे जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों ना की जाये?

इस मामले में याचिकाकर्ता हरि प्रसाद शर्मा की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा पेश हुए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि दिसम्बर माह में तत्कालीन नगर पालिका ने उसे व कई अन्य को नोटिस दिया था कि सड़क पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को हटा लिया जाये, जबकि याचिकाकर्ता ने कभी भी किसी भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं किया और अपने ही स्वामित्व की जमीन पर काबिज था।

फिर भी याचिकाकर्ता का मकान नगर पालिका ने अगस्त में बिना नोटिस दिए 25 फीट तक तोड़ दिया और इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने जनवरी माह में नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि प्रशासन ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि उक्त क्षेत्र में कई मकानों का ध्वस्त किया जाएगा।

इसी मामले में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष भी अपील दायर की थी ताकि उन्हें नगर परिषद द्वारा किसी भी कार्यवाही के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा के रुप में स्टे मिल सके।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 25 फरवरी 2022 को याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता तथा अन्य संबंधित मामलों में नगर परिषद नये नोटिस जारी करे और एक माह में उनकी आपत्तियां सुनकर उनका निस्तारण करके ही आगे कोई कार्यवाही करे।

अदालत ने कहा था कि सभी संबंधित मामलों में दुकानदारों व मकान मालिकों को नगर परिषद के किसी भी फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती देने के लिये 15 दिन का समय भी दिया जाता है।

याचिकाकर्ता हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि नगर परिषद ने हाईकोर्ट के 25 फरवरी को दिये गये फैसले की अवहेलना करते हुए उन्हें कभी कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही सुनवाई की और उनके मकान को 25 फीट अंदर तक तोड़ दिया। जिसकी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किये।

## जालोर में...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

विभिन्न भागों से प्रवासी पक्षियों का भारत की और आना प्रारंभ होता है। हजारों किलोमीटर की लंबी दुर्गम सुदूर यात्रा कर यह पक्षी भारत आते हैं।

तालाब पानी के आस-पास रहने वाली कई पक्षी-प्रजातियाँ केवल छिछले पानी में पाई जाती हैं। इस दृष्टि से सुन्देलाव तालाब अत्यंत अनुकूल है। तालाब के कई हिस्सों में आधा फुट से कम पानी है। ऐसे हिस्सों को वैटलैंड भी कह सकते हैं। इसलिए, इसके आस-पास पर्याप्त जैव-विविधता है। अमूर फाल्कन का अपनी यात्रा के दौरान यहाँ रूकना एक शुभ संकेत है। तालाब का प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखने के लिए इसे कचरे और मानवीय हस्तक्षेप से बचाने की आवश्यकता है।

## तेलंगाना के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

प्रवृत्ति भी दिखाई दी है कि भाजपा ऐसा कोई उपचुनाव नहीं जीत पाई है, जो उसने राज्य पर जबरदस्ती थोपा है। इस विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक से भाजपा ने पार्टी तथा इस सीट से इस्तीफा दिलाकर, यह सीट खाली कराई थी। इस प्रकार, यह चुनाव वस्तुतः राज्य पर भाजपा द्वारा थोपा गया चुनाव था तथा टी.आर.एस. ने भाजपा के इस षडयंत्र को जनता के सामने खोलकर रख दिया था। लेकिन भाजपा इस रूप में जरूर अपनी योजना में कामयाब रही कि उसने कांग्रेस के इस ताकतवर विधायक को उससे दूर करके, पहले ही कमजोर हो चुकी कांग्रेस को और भी कमजोर कर दिया।

भाजपा की चालाकी और चालबाजी का उसी की भाषा में जवाब देने के लिये, टी.आर.एस. ने भी एक खेल खेला। उसने अपने विधायकों को कथित रूप से खरीदे जाने का आरोप भाजपा पर लगा डाला तथा इस प्रकार इस उपचुनाव में, अवधारणा निर्मित करने की युक्ति और लड़ाई भी अस्तित्व में आई।

टी.आर.एस. और तेलंगाना सरकार ने अपनी पूरी ताकत प्रचार-प्रसार एवं दुष्प्रचार में लगाते हुये, भाजपा पर सीधे प्रहार किये तथा चुनाव से एक दिन पूर्व राजनैतिक स्टंट और धन बल के खुले खेल के सहारे इस उपचुनाव में, मामूली अंतर से ही सही, कामयाबी हासिल कर ली।

10,000 वोटों के मामूली अंतर से मिली इस जीत में, कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस को महसूस हो गया गया था कि वह इस सीट को जीतने की स्थिति में नहीं है तथा इसलिये अपना ध्यान भाजपा को हराने पर अपने दलबदलू नेता, भाजपा प्रत्याशी राजगोपाल रेड्डी को सबक सिखाने पर ध्यान केन्द्रित किया।

जहाँ तक सत्तारूढ़ टी.आर.एस. का प्रश्न है, मुनुगोड उपचुनाव का परिणाम उसे झकझोर कर जगाने का काम करेगा।

यह परिणाम साफ इशारा कर रहा है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनावों में होने वाली लड़ाई किस किस्म की तथा किस रूप में होगी। उन चुनावों में, टी.आर.एस. को एक कृत संकल्प भाजपा से लड़ना होगा, जो राज्य में दिन-पर-दिन आगे बढ़ती जा रही है।

## सुप्रीम कोर्ट के निर्णय...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

"भेदभाव के संवैधानिक रूप से निषिद्ध स्वरूपों" के समान है।

कापू, जाट, मराठा या पाटीदार सहित विभिन्न समुदायों की आरक्षण की माँगे अब तक इसी आधार पर खारिज की जाती रही है कि 50 प्रतिशत कोटा की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में, इन माँगों के पुर्नजीवित संभावना है।

- **पर, जैसा कि, माना जाता है, असल में ओ.बी.सी. समुदाय की जनसंख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है, अतः अगर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना तय किया जायेगा, तो ओ.बी.सी. को ही शिक्षा व रोजगार में दिया जा रहा 27 प्रतिशत का आरक्षण बढ़ाने की मांग जोरों से उठेगी।**

ब्रिटिश शासनकाल में भी एस.सी./एस.टी. को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप आरक्षण दिया जाता था। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ओ.बी.सी. को केवल 27 प्रतिशत आरक्षण ही दिया गया, जबकि अनधिकृत अनुमानों के अनुसार, ओ.बी.सी. भारत की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से ज्यादा है। स्वतंत्र भारत में, जातिगत जनगणना जैसी कोई चीज नहीं हुई। अंतिम जातिगत गणना बहुत पहले 1931 में हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले के साथ ही, इस बात की पूरी संभावना है कि ओ.बी.सी. नेता एवं समुदाय, अपनी जनसंख्या के हिसाब से शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने की माँग के आंदोलन पुनः शुरु एवं तेज कर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपनी अर्ज़ी में, केन्द्र सरकार ने ई.डब्ल्यु.एस. श्रेणी की संख्या का अनुमान तथा ई.डब्ल्यु.एस. श्रेणी के आरक्षण के पात्र लोगों के बारे में तय की गई अपनी रणनीति के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसलिये, ई.डब्ल्यु.एस. श्रेणी की आरक्षण-व्यवस्था के क्रियान्वयन में समस्या होने की संभावना है।

## मु.मंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, 7 नवंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग और खनन पट्टा हासिल करने के आरोपों पर सोमवार को राहत का फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मुख्यमंत्री सोरेन को उनकी और राज्य सरकार की अपील पर राहत दी। पीठ ने मुख्यमंत्री सोरेन पर मुखौटा (शेल) कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग और खुद के लिए एक खनन पट्टा हासिल करने के आरोपों के संबंध में दायरा जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य करार देने के झारखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ की ओर न्यायमूर्ति धूलिया ने यह फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री सोरेन ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

## 50 पाक ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

पचास लोगों का एक जत्था कल रात जम्मू तवी एक्सप्रेस के जरिये बड़ी संख्या में पाक विस्थापितों के पहुंचने की सूचना मिलते ही सीआईडी की एक टीम रेलवे स्टेशन पहुंच गई। इस टीम ने सभी को एक तरफ बैठा दो घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में सामने आया कि ये लोग पाकिस्तान से धार्मिक वीजा के आधार पर वाघा बॉर्डर से अटारी पहुंचे। अटारी से हरिद्वार जाने के बजाय ये लोग सीधे जोधपुर आ गए। जोधपुर पहुंचने के पीछे इनका तर्क है कि ये लोग यहां पर रहने के लिए आए है। सिर्फ धार्मिक वीजा के नाम पर ही आने की अनुमति मिलती है। ऐसे में इस अनुमति के आधार पर भारत में प्रवेश कर ये लोग जोधपुर आ गए। पाक विस्थापित एक वाहन में सवार होकर अपने रिश्तेदार के यहां चले गए।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में बरसों से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने वाले पाक हिन्दू भारत आना चाहते है, लेकिन वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता।

भारत में प्रवेश करने के बाद हरिद्वार के अलावा अन्य किसी भी शहर में जाने के लिए एडिशनल वीजा लेना पड़ता है। एडिशनल वीजा मिलने के बाद ही ये लोग उसमें दी गई अनुमति के आधार पर अन्य स्थान पर जा सकते है। इसके बाद ही इन लोगों को लॉग टर्म भारत में रहने का वीजा मिलता है, जिसके आधार पर बाद में तय शर्तें पूरी कर ये लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते है।

बताया जा रहा है कि 36 पासपोर्ट धारकों का एक रिश्तेदार देचू के समीप एक खेत में काम करता है।

ये सभी लोग उसके पास गए है। अन्य 14 पासपोर्ट धारक जोधपुर में अपने एक रिश्तेदार के पास ठहरे है।

# आयकर छापे में तीन व्यापारियों के पास 70 करोड़ रू. की अघोषित संपत्ति मिली

- **सबसे ज्यादा, 52 करोड़ रूपये नोखा के झंवर ग्रुप के पास मिले।**
- **बीकानेर के व्यापारी जुगल राठी के यहां दस करोड़ और धनपत चायल के यहां आठ करोड़ रूपये की अघोषित रकम मिली।**

बीकानेर, 7 नवम्बर (कासं)। बीकानेर जिले के तीन व्यापारियों के चालीस ठिकानों पर हुई छापेमारी की कार्रवाई में आयकर विभाग को करीब 70 करोड़ रूपये की अघोषित आय मिली है।

इसमें सर्वाधिक 52 करोड़ रूपये की अघोषित आय नोखा के श्रीनिवास झंवर के यहां मिली है। जबकि बीकानेर के व्यापारी जुगल राठी के यहां दस करोड़ और धनपत चायल के यहां आठ करोड़ रूपये की अघोषित आय मिली है। छानबीन पूरी होने के साथ ही अधिकारी वापस लौट गए हैं लेकिन जांच में ये अघोषित आय घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने चार दिन तक लगातार छापेमारी करते हुए रिकॉर्ड्स एकत्रित किए। इस दौरान बैंकों में लॉकर भी व घरों में यहां-वहां एक-एक कागज को खंगाला गया। तीनों व्यापारियों के करीब चालीस ठिकानों पर हुई कार्रवाई में अघोषित संपत्ति का पता लगाया गया। सबसे ज्यादा नोखा के व्यापारी श्रीनिवास झंवर के आवास व ऑफिस में मिला।

इस दौरान कई जमीनों के कागजात भी आयकर विभाग ने कब्जे में लिए हैं। वहीं नकद राशि, जेवरात भी रिकॉर्ड पर लिए गए हैं। श्रीनिवास झंवर और उनसे जुड़े दस लोगों के यहां रिकॉर्ड की छानबीन की गई। नोखा में इनकम टैक्स की कार्रवाई में ये सबसे बड़ी अघोषित आय मानी जा रही है।

बीकानेर के दो व्यापारियों जुगल राठी और धनपत चायल के यहां भी कार्रवाई पूरी हो गई है। दोनों व्यापारियों के घर और ऑफिस के अलावा उनसे जुड़े करीब तीस ठिकानों पर एक साथ सर्च शुरू की गई।

इस दौरान जुगल राठी के यहां दस करोड़ रूपये की अघोषित आय मिली है, जबकि धनपत चायल के यहां आठ करोड़ रूपये की अघोषित आय मिलने की सूचना है। आयकर विभाग ने दोनों व्यापारियों के यहां से जो कागजात लिए हैं, अब उनकी छानबीन की जायेगी।

# कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैण्डल पर प्रतिबंध लगा

- **फिल्म के.जी.एफ. चैप्टर-2 फेम म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ बैंगलुरु की एक कर्मशियल कोर्ट में बिना इजाज़त के फिल्म का म्यूजिक एवं गाने इस्तेमाल करने की शिकायत की थी।**

बैंगलुरु, 7 नवम्बर। बैंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैण्डल को अस्थाई रुप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित एक वीडियो तैयार किया था। म्यूजिक लेबल का दावा है कि, उनकी फिल्म के गानों का इस वीडियो के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके सभी म्यूजिक राइट्स उनके पास हैं।

बैंगुलुरु की एक कमर्शियल कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थाई रूप से ब्लॉक किया जाए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा।

कोर्ट ने आगे कहा, 'शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से सीडी पेश की और अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ मूल गाने को दिखाया।

कोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो वादी को सिनेमैटोग्राफी, फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम को प्राप्त करने के लिए बिजनेस में नुकसान होगा। साथ ही आगे भी पाइरेसी को प्रोत्साहन मिलेगा।'

## दक्षिण भारत जायेंगे मोदी

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। वे गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के बीच ही चार दक्षिण भारतीय राज्यों की यात्रा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी जिन राज्यों में जाएंगे, वह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। जानकारी के मुताबिक, वे 11 नवंबर को कर्नाटक और तमिलनाडु जाएंगे।

इसके बाद 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार 11 नवंबर को सुबह 09:45 बजे केएसआर रेलवे स्टेशन बैंगलुरू पर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे।

# हमलावर की गोली से घायल इमरान...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कर दी हैं।

इमरान के प्रचार-अभियान के दो प्रमुख आधार या मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि अमेरिका उन्हें पाकिस्तान की सत्ता से बाहर रखना चाहता है तथा यही कारण है कि उन छोटे-मोटे दलों के अलावा सभी बड़े राजनैतिक दल, जैसे-पाकिस्तान पीपुल पार्टी तथा मुस्लिम लीग-उनका विरोध कर रही हैं।

पी.टी.आई. तथा अमेरिका के बीच विरोध उस समय शुरू हुआ, जब इमरान खान ने अफगान-युद्ध में अमेरिका तथा नाटो ताकतों को पारगमन सुविधाएं (ट्रांज़िट फैसिलिटीज) देते रहने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद, इमरान ने यह बयान दिया था कि अफगान-युद्ध 'एक अन्य देश का युद्ध" है। इसलिये, पाकिस्तान इसमें क्यों उलझे।

इसलिये अमेरिका के सामने गम्भीर समस्या खड़ी हो गई थी तथा एक प्रकार से, यह समस्या ही अफगानिस्तान से अमेरिका की अपमानजनक वापसी का एक कारण बन गई थी।

इस सन्दर्भ में, इमरान द्वारा युक्रेन-युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति की मुक्त कंठ से की गई प्रशंसा भी उल्लेखनीय है।

(ज्ञातव्य है कि दोनों ही) पक्ष भारत का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इमरान ने भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदते रहने तथा हमले के लिये रूस की निन्दा करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिये जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया था। इमरान ने उस समय कहा था भारत "एक स्वतन्त्र देश के लिये उपयुक्त स्वतन्त्र विदेश नीति" पर चल रहा है।

पाकिस्तान के सामान्य लोगों ने अफगान युद्ध पर इमरान खान के रूख तथा अपनी "स्वतन्त्र" विदेश नीति पर जमे रहने की कोशिश को सिर-आँखों पर लिया था। इस नीति का सार तत्व यह था कि अमेरिकन सेना द्वारा अमेरिका के रूख का समर्थन किया जाना स्वाभाविक था तथा इसलिये अमेरिकन सेना इमरान का विरोध करती रही, जिसका अन्त इमरान सरकार के गिर जाने के रूप में हुआ।

पाकिस्तानी सेना का एक मात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य भारत का विरोध करना रहा है तथा इन्ही प्रयासों के अन्तर्गत, पाकिस्तानी सेना अमेरिका से अत्याधुनिक एवं उन्नत किस्म के हथियारों की माँग करती रहती हैं तथा उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करती रहती है। इसका एक उदाहरण, पाकिस्तानी सेना द्वारा एफ-16 जैसा आक्रामक एयरक्राफ्ट प्राप्त करना था।

यहाँ यह भी याद रखा जाना चाहिये कि अमेरिका अभी हाल ही में पाकिस्तान के एफ-16 बेड़े के महत्वपूर्ण कल-पुर्जो तथा पूरे एयरक्राफ्ट तन्त्र की सप्लाई की मंजूरी दी है क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद तथा उनके कार्यकाल में इससे इनकार कर दिया गया था। ट्रम्प ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता तथा पाकिस्तान को दिये जाने वाले अत्यावश्यक उपकरणों बन्द कर दी थी। इमरान की वाशिंगटन जाकर ट्रम्प से भेंट करने की तमाम कोशिशों के बाद भी, ट्रम्प ने उनसे मिलने से इकार कर दिया था।

इमरान को हटाए जाने और शाहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद ही अमेरिका ने एक बार फिर 450 मिलियन डॉलर एफ-16 सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया।

बाइडन सरकार द्वारा इस डील को मंजूरी देने से भारत बहुत नाराज हुआ और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस डील की कड़ी निंदा की और वॉशिंगटन में ही इस डील के खिलाफ बयान भी दिया।

इमरान खान की अमेरिका विरोधी नीति ने उन्हें सत्ता से बाहर किया था और इस नीति को जनता का भारी समर्थन मिला है।

सबसे पहले तो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को इस्लाम के खिलाफ माना गया और इस बात ने यहां की जनता को बहुत प्रभावित किया।

यही नही दुनिया के अन्य भागों में बसे पाकिस्तानियों ने भी इमरान खान के प्रति भारी समर्थन दर्शाया और इमरान जब सत्ता में थे तो उन्होंने भारी धनराशि भेजी। इमरान के कार्यकाल में ही पाकिस्तान को दुनिया भर के पाकिस्तानियों से सर्वाधिक मदद मिली।

हालांकि इस समय पाकिस्तान में जो गंभीर आर्थिक संकट है उसमें ही इमरान का हित है। पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने का पैसा भी नही है और वह आई.एम.एल. से मदद की आस लगाए है।

## अखिलेश ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

के सबसे सीनियर पूर्व छात्रों ने किया। उसके बाद वर्तमान छात्रों ने ही स्कूल बैंड बजाया।

मुख्य आतिथि व सभी मेहमानों ने वर्तमान छात्रों की जम के तारीफ़ की। पूर्व छात्रों ने स्कूल के एक गार्ड रूम का उद्घाटन किया। पूर्व छात्रों ने अपने पुराने दिनों की याद में छोटे-छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अखिलेश यादव ने छात्रों को पुरुस्कार दिए। प्राचार्य लैफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टी. पी. ने भी मुख्य अतिथि अखिलेश यादव को उनके इस क्षण को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह के साथ एक पोस्टर दिया। इस पोस्टर में उनके द्वारा विद्यालय में बिताये गए दिनों के कुछ फोटोज का कोलाज बना हुआ था और उनका आभार व्यक्त किया गया।

अंत में मुख्य अतिथि अखिलेश यादव ने छात्रों को कड़ी मेहनत करने और जीवन में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया और एक छात्र के रूप में स्कूल में बिताए अपने दिनों को भी साझा किया।

# यूक्रेन व रूस के बीच...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

की एक प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार विविध कार्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दो पर चर्चा की जाएगी।

वॉशिंगटन स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट-एशियन स्टडीज़ सैन्टर एट द हैरिटेज फाउण्डेशन के निदेशक जैफ एम. स्मिथ ने कहा कि "चूंकि भारत की दोनों पक्षों तक पहुंच है, इसलिए उसे एक संभावित शांति स्थापक के रूप में उत्तरोत्तर देखा जा रहा है। यदि रूस और यूक्रेन एक तटस्थ थर्ड पार्टी मध्यस्थ में अपनी रूचि दर्शाते हैं तो भारत इसके लिए एक मजबूत प्रत्याशी होगा क्योंकि उसे दोनों पक्षों से विश्वसनीयता प्राप्त है।"

एन. वॉय. टी. की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति पुतिन से अच्छे संबंध हैं और वह रूस से सीधे बात कर सकते हैं। हालांकि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और उसके खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्तावों का समर्थन करने से इनकार कर रहा है, जिससे यूक्रेन और अमेरिका आक्रोशित हैं, लेकिन भारत का मानना है कि रूस को कोसने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, जबकि सार्वजनिक रूप से तटस्थ रहना युद्ध समाप्ति के प्रयासों के लिए उपयोगी हो सकता है।

खबर में बताया गया कि गत सितम्बर माह में उज़बेकिस्तान में आयोजित एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। उन्होने पुतिन से कहा था कि "आज का युग युद्ध का नहीं है" वह चाहते हैं कि इस पर चर्चा की जाए कि हम शांति के मार्ग पर किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। खबर में मोदी को पिछले कई दशकों में भारत के सर्वाधिक सशक्त प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हुए कहा गया कि वह भारत की गुटनिरपेक्ष परम्परा को नए सिरे से गढ़ कर सभी के साथ वाली अधिक प्रभावशाली रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह दुनिया के सबसे बड़े संकट को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगता है कि इतिहास में भारत के महानतन नेताओं में से एक बनने की उनकी महत्वाकांक्षा के उपयुक्त है।

कूटनीतिज्ञ कहते हैं कि वर्तमान घटनाक्रम का एक अन्य आयाम यह है कि भारत, इज़रायल और यू.ए.ई. द्वारा संयुक्त मध्यस्थता के प्रयास हो सकते हैं। अखबार ने भारत में पूर्व राजदूत रहे कैनथ जस्टर को उद्धृत करते हुए कहा कि इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि "ये तीनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे और यूक्रेन के साथ विवाद को लेकर संभवतया रूस का रूख करेंगे। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिस्टम के लचीलेपन और उसमें आए बदलावों को स्पष्ट करता है।"

कैनथ जस्टर ने आगे कहा कि भारतीय विदेश सेवा में काफी दक्ष राजनयिक हैं, और यदि वे रूस व यूक्रेन के राजी होने पर वार्ताओं में सहयोग का ऑफर देते हैं तो अच्छा होगा।

खबर में बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा भारतीयों की प्रशंसा किए जाने के बाद जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। गत 4 नवम्बर को रूस के एकता दिवस के मौके पर पुतिन ने कहा था कि "भारत में निः सन्देह इनती क्षमता है कि वह विकास के सन्दर्भ में उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर सकता है। रूसी भाषा में मूल रूप से दिए गए इस भाषण रॉयटर एजेंसी द्वारा किए गए अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि "भारत विकास के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं और डेढ़ अरब लोग ही उसकी वह क्षमता हैं।

राष्ट्रदूत ( एच.यू.एफ. ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908